

जापान की आधिकारिक विकास सहायता

प्रलिम्स के लिये:

भारत-जापान संबंध, जलवायु परिवर्तन, पटना मेट्रो, वेस्टर्न डेडकिंटेड फ्रेट कॉरडोर

मेन्स के लिये:

जापान की आधिकारिक विकास सहायता, भारत-जापान संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान ने भारत में कुछ प्रमुख परियोजनाओं के लिये [आधिकारिक विकास सहायता](#) (Official Development Assistance- ODA) को मंजूरी दी है।

- वर्ष 1958 से ही **भारत और जापान** के बीच द्विपक्षीय विकास सहयोग का महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। पछिले कुछ वर्षों में भारत एवं जापान के बीच आर्थिक सहयोग में लगातार वृद्धि देखने को मिली है।



आधिकारिक विकास सहायता के तहत प्रमुख परियोजनाएँ:

- **पटना मेट्रो रेल नरिमाण पररिओजना:**
 - पटना मेट्रो रेल नरिमाण पररिओजना (I) के लरि 5,509 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है ।
 - इसका उद्देश्य नए मेट्रो कॉरडोर का नरिमाण करके पटना में यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करना है, ताका शहरी पर्यावरण में सुधार और अर्थव्यवस्था के वकिस के साथ-साथ **जलवायु पररिर्तन** के शमन में योगदान दया जा सके ।
- **पश्चमि बंगाल में वन और जैववविधिता संरक्षण:**
 - जलवायु पररिर्तन परतक्रिया के लरि पश्चमि बंगाल में वन एवं जैववविधिता संरक्षण पररिओजना हेतु लगभग 520 करोड़ रुपए मंजूर कया गए हैं ।
 - इसका उद्देश्य जलवायु पररिर्तन को कम करना एवं अनुकूल बनाना, पारस्थितिक तंत्र आधारति जलवायु पररिर्तन उपायों, जैववविधिता संरक्षण तथा बहाली द्वारा पारस्थितिक तंत्र को संरक्षति और पुनरस्थापति करना है, ताका राज्य में सतत् सामाजकि-आर्थकि वकिस में योगदान दया जा सके ।
- **राजस्थान जल क्षेत्र आजीवकि सुधार प्रोजेक्ट:**
 - **राजस्थान जल क्षेत्र आजीवकि सुधार पररिओजना (द्वतीय) हेतु 1,055.53 करोड़ रुपए** स्वीकृत कया गए हैं ।
 - इसका उद्देश्य मौजूदा सचिई सुवधियों और कृषि सहायता सेवाओं में सुधार के माध्यम से जल उपयोग दक्षता एवं कृषि उत्पादकता में सुधार कर राज्य में कृषि तथा सचिई क्षेत्र में महिलाओं की भूमकि को बढ़ावा देने के साथ-साथ कसिानों की आजीवकि में सुधार करना है ।

जापान द्वारा भारत हेतु अन्य ODA:

- **दलिली मेट्रो द्वारा ODA का उपयोग जापानी सहयोग के सबसे सफल उदाहरणों में से एक है ।**
- भारत की **वेसटरन डेडकिंटेड फरेट कॉरडोर (DFC)** पररिओजना हेतु जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा आर्थकि साझेदारी के लरि वशिष शर्तों (Special terms for Economic Partnership- STEP) के तहत उदार ऋण प्रदान कया गए हैं ।
- इसके अलावा जापान और भारत, **जापान के शकिनसेन ससि्टम** का उपयोग करके **भारत में हाई-स्पीड रेलवे** के नरिमाण पर सहमत हुए ।
- **भारत-जापान परमाणु समझौता 2016** भारत को दक्षिणी भारत में छह परमाणु ररिक्टर बनाने में मदद करेगा, जसिसे वर्ष 2032 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता दस गुना बढ़ जाएगी ।

UPSC सवलिल सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. 'भारत और जापान के लरि समय आ गया है कएक ऐसे मज़बूत समसामयकि संबंध का नरिमाण करें, जसिका वैश्वकि एवं रणनीतिक साझेदारी को आवेष्टति करते हुए एशिया एवं संपूर्ण वशिव के लरि बड़ा महत्त्व होगा ।' टपिपणी कीजयि । (2019)

स्रोत: पी.आई.बी.